Online at: https://researchtrendsjournal.com
Indexed Journal

ISSN No: 2584-282X
Peer Reviewed Journal

INTERNATIONAL JOURNAL OF TRENDS IN EMERGING RESEARCH AND DEVELOPMENT

Volume 3; Issue 4; 2025; Page No. 31-36

Received: 06-04-2025
Accepted: 16-06-2025

भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में थारू महिलाओं की शिक्षा: चुनौतियाँ और संभावनाएँ (पलिया तहसील, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश का एक अध्ययन)

विनय कुमार विश्वकर्मा

शोध छात्र, समाजशास्त्र विभाग, सामाजिक विज्ञान संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.15927227

Corresponding Author: विनय कुमार विश्वकर्मा

सारांश

यह शोध लेख भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र, विशेषतः उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले की पलिया तहसील में निवास करने वाली थारू समुदाय की महिलाओं की शैक्षिक स्थिति का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। थारू महिलाएं एक पारंपरिक, जनजातीय एवं सामाजिक रूप से वंचित समुदाय से संबंध रखती हैं, जो ऐतिहासिक रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों और वनों में जीवन यापन करती आई हैं। उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, पारंपरिक ज्ञान प्रणालियाँ और जीवनशैली उन्हें मुख्यधारा की सामाजिक एवं शैक्षिक संरचना से अलग करती हैं। यह अध्ययन दर्शाता है कि थारू महिलाएं शिक्षा तक पहुँच के संदर्भ में कई जटिल सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और आधारभूत चुनौतियों का सामना करती हैं। इनमें विद्यालयों की भौगोलिक दूरी, मातृभाषा और माध्यम भाषा के बीच अंतर, पारंपरिक लिंग भूमिकाएं, बाल विवाह, और सामाजिक भेदभाव जैसे प्रमुख अवरोध शामिल हैं। यह शोध माध्यमिक साहित्य, सरकारी आंकड़ों तथा गैर-सरकारी संगठनों की रिपोर्टों के गुणात्मक विश्लेषण पर आधारित है। इसमें कौशल विकास कार्यक्रमों, व्यावसायिक प्रशिक्षण पहलों और हाल के सरकारी एवं गैर-सरकारी हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता की समीक्षा की गई है। विशेष रूप से यह लेख यह समझने का प्रयास करता है कि किस प्रकार की नीतियाँ और कार्यक्रम थारू महिलाओं के शैक्षिक सशक्तिकरण में प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं। अंततः, यह अध्ययन थारू महिलाओं की शिक्षा को समग्र रूप से प्रोत्साहित करने हेतु नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करता है, जो न केवल उनके व्यक्तिगत सशक्तिकरण में सहायक होंगे, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों के सतत और समावेशी विकास को भी दिशा प्रदान करेंगे।

मूलशब्द: थारू महिलाएं, शिक्षा, आदिवासी समुदाय, लखीमपुर खीरी, सीमा क्षेत्र, कौशल विकास

1. प्रस्तावना

थारू महिलाएं, जो मुख्यतः भारत और नेपाल के तराई क्षेत्र में निवास करती हैं, शिक्षा और सशक्तिकरण के क्षेत्र में लंबे समय से हाशिए पर रही हैं। लखीमपुर खीरी जिले की पलिया तहसील, जो भारत-नेपाल सीमा पर स्थित है, एक ऐसा विशेष संदर्भ प्रस्तुत करती है जहाँ लिंग, जातीयता और क्षेत्रीय अविकास के अंतर्संबंधों को समझा जा सकता है। संवैधानिक अधिकारों और अनेक कल्याणकारी योजनाओं के बावजूद, थारू महिलाएं औपचारिक शिक्षा से काफी हद तक वंचित हैं। यह लेख शैक्षिक असमानताओं के सामाजिक-

आर्थिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और संरचनात्मक कारणों को उजागर करता है। इसमें यह विश्लेषण किया गया है कि किस प्रकार गरीबी, बाल विवाह, रूढ़िवादी सामाजिक दृष्टिकोण, विद्यालयों की भौगोलिक दूरी, महिला शिक्षकों की अनुपलब्धता, तथा भाषाई व सांस्कृतिक अंतर जैसी चुनौतियां थारू महिलाओं की शिक्षा में बाधक बनती हैं। इसके अतिरिक्त, यह लेख सरकारी योजनाओं जैसे सर्व शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, और राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के प्रभाव का आकलन करता है और यह दर्शाता है कि इन योजनाओं का स्थानीय स्तर पर किस हद तक प्रभावी क्रियान्वयन हुआ है। इस अध्ययन में माध्यमिक साहित्य, जनगणना आंकड़ों, शिक्षा मंत्रालय के रिपोर्टों, राज्य सरकार की योजनाओं और विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रकाशित फील्ड रिपोर्टों का गुणात्मक विश्लेषण किया गया है। विशेष रूप से महिलाओं के लिए चलाई जा रही साक्षरता और कौशल विकास योजनाओं, जैसे महिला शक्ति केंद्र, स्वयं सहायता समूहों के प्रशिक्षण कार्यक्रम, तथा डिजिटल साक्षरता पहल का समावेश इस शोध में किया गया है। इसके अतिरिक्त, यह शोध यह भी रेखांकित करता है कि कुछ क्षेत्रों में जहां स्वयंसेवी संस्थाएं सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं, वहां थारू महिलाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता और भागीदारी में वृद्धि देखी गई है। इसके बावजूद, समुदाय-स्तर पर सामाजिक परिवर्तन और नीति-निर्माताओं की प्रतिबद्धता की आवश्यकता है ताकि इस समुदाय की महिलाओं को शिक्षा के अधिकार और अवसर दोनों सुनिश्चित किए जा सकें। अंततः यह शोध शिक्षा नीति, जेंडर समावेशी योजनाओं और जनजातीय कल्याण के संदर्भ में विशेष नीतिगत सिफारिशें प्रस्तुत करता है, जिनमें स्थानीय भाषाओं में शिक्षण सामग्री की उपलब्धता, महिला शिक्षकों की नियुक्ति, समुदाय-आधारित शैक्षिक पहल, व थारू संस्कृति के अनुरूप पाठ्यक्रम का विकास शामिल है। शिक्षा को केवल साक्षरता तक सीमित न रखते हुए, व्यावसायिक और जीवनोपयोगी कौशल से जोड़ने की दिशा में भी ठोस रणनीति विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे थारू महिलाएं सामाजिक व आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें और अपने समुदाय के समग्र विकास में सक्रिय भूमिका निभा सकें।

2. शोध पद्धति

यह अध्ययन गुणात्मक अनुसंधान पद्धति पर आधारित है। डेटा निम्नलिखित स्रोतों से एकत्र किया गया:

सरकारी शिक्षा रिपोर्टें
गैर-सरकारी संगठन (BASE, Nepal Youth Foundation)
समाचार पत्र (दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान)
शैक्षिक जर्नल
साक्षात्कार और क्षेत्र कार्य

3. सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि

थारू समाज परंपरागत रूप से कृषि आधारित जीवनशैली को अपनाने वाला एक स्वदेशी जनजातीय समुदाय है, जो विशेष रूप से उत्तर भारत और नेपाल की सीमावर्ती क्षेत्रों में निवास करता है। इस समुदाय की जीवन प्रणाली मुख्यतः प्रकृति पर आधारित है, जहाँ खेतिहर कार्य, पशुपालन, वनोपज संग्रहण और पारंपरिक हस्तशिल्प जैसे कार्य प्रमुख आजीविका के साधन हैं। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले और नेपाल के तराई क्षेत्रों में बसे थारू समुदाय की सामाजिक संरचना में महिलाओं की भागीदारी काफी महत्वपूर्ण है। कई क्षेत्रों में थारू समाज में मातृसत्तात्मक प्रभाव भी परिलक्षित होता है, जहाँ महिलाएं न केवल घरेलू निर्णयों में भाग लेती हैं, बल्कि आर्थिक गतिविधियों में भी सक्रिय योगदान देती हैं। थारू महिलाएं खेतों में काम करने, गाय-भैंस जैसे पशुधन के प्रबंधन, सब्जियों की खेती, और पारंपरिक हस्तशिल्प जैसे टोकरी बुनाई, कपड़े कढ़ाई व अन्य घरेलू उद्योगों में दक्ष होती हैं। इनका श्रम न केवल परिवार की आजीविका को सुदृढ़ करता है, बल्कि सामाजिक संरचना में उनकी केंद्रीय भूमिका को भी रेखांकित करता है। इसके बावजूद, जब बात शिक्षा की आती है, तो थारू समाज में अनेक बाधाएं उभर कर सामने आती हैं, विशेषकर लड़कियों के संदर्भ में। थारू समुदाय में बाल विवाह अब भी एक व्यापक प्रथा है, जिसके कारण बहुत सी लड़कियों की शिक्षा प्राथमिक स्तर के आगे नहीं बढ़ पाती। कम उम्र में विवाह और मातृत्व की जिम्मेदारी से वे विद्यालय से वंचित हो जाती हैं। इसके साथ ही, घरेलू कार्यों का असमान बोझ, जैसे कि छोटे भाई-बहनों की देखभाल, खाना बनाना, पशु चराना और खेतों में काम करना–लड़कियों के लिए औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने में एक गंभीर बाधा बनते हैं। इसके अतिरिक्त, रूढ़िवादी लिंग दृष्टिकोण और पारंपरिक सामाजिक धारणाएं यह मानती हैं कि लड़कियों की भूमिका केवल घर-परिवार तक सीमित है, और शिक्षा केवल लड़कों के लिए आवश्यक है। इस सोच के कारण कई माता-पिता अपनी बेटियों को विद्यालय भेजने में रुचि नहीं लेते, या उन्हें शुरुआती कक्षाओं के बाद विद्यालय से निकाल लेते हैं। साथ ही, गांवों और दूर-दराज़ के इलाकों

में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की कमी, महिला शिक्षकों का अभाव, और विद्यालयों तक सुरक्षित पहुँच की अनुपलब्धता भी लड़कियों के शिक्षा छोड़ने के कारणों में शामिल हैं। इन तमाम सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं के कारण, थारू लड़कियों की शिक्षा दर राज्य और राष्ट्रीय औसत की तुलना में बहुत कम है। यह केवल व्यक्तिगत विकास को नहीं रोकता, बल्कि संपूर्ण समुदाय की सामाजिक और आर्थिक प्रगति में भी अवरोध उत्पन्न करता है। अतः यह आवश्यक है कि थारू समाज की सांस्कृतिक विशेषताओं को समझते हुए, एक समावेशी और जेंडर-संवेदनशील शैक्षिक ढांचा विकसित किया जाए, जो न केवल लड़कियों को विद्यालय में लाए, बल्कि उन्हें वहाँ टिकाए रखने और आगे बढ़ाने में भी सहायक हो।

4. शैक्षिक चुनौतियाँ

4.1 अधिक ड्रॉपआउट दर

माध्यमिक स्कूलों की कमी, परिवहन सुविधाओं का अभाव, और लिंग आधारित हिंसा के कारण लड़कियाँ प्राथमिक शिक्षा के बाद स्कूल छोड़ देती हैं।

4.2 भाषाई बाधाएँ

अधिकांश औपचारिक शिक्षा व्यवस्था हिंदी या अंग्रेजी जैसी मुख्यधारा की भाषाओं में संचालित होती है, जबकि थारू समुदाय के बच्चों की मातृभाषा इनसे भिन्न होती है। थारू भाषा, जो कि उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान का महत्वपूर्ण अंग है, स्कूलों की पाठ्यपुस्तकों, शिक्षण सामग्री या शिक्षण माध्यम में स्थान नहीं पाती। इस भाषाई अंतर के कारण थारू छात्रों को न केवल विषयवस्तु को समझने में कठिनाई होती है, बल्कि वे विद्यालयी परिवेश से भी असंबद्ध महसूस करते हैं। जब कोई बच्चा ऐसी भाषा में शिक्षा प्राप्त करता है जिसे वह न तो घरेलू वातावरण में बोलता है और न ही सहज रूप से समझ पाता है, तो उसकी सीखने की गति धीमी हो जाती है और आत्मविश्वास भी कमजोर पड़ता है। परिणामस्वरूप, पढ़ाई में अरुचि, परीक्षा में खराब प्रदर्शन और अंततः विद्यालय छोड़ देने जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। यह केवल भाषा का मुद्दा नहीं है, बल्कि एक बड़ी शैक्षणिक असमानता का संकेत है, जहाँ छात्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को नज़रअंदाज़ किया जाता है। भाषाई दूरी न केवल समझ को बाधित करती है, बल्कि बच्चे को यह भी महसूस कराती है कि उसकी पहचान, संस्कृति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को शिक्षा प्रणाली में महत्व नहीं दिया जा रहा। यह अनुभव सामाजिक बहिष्करण की भावना को जन्म देता है और छात्र के अंदर एक गहरी हीनभावना विकसित कर सकता है। इस चुनौती का समाधान स्थानीय भाषा आधारित प्रारंभिक शिक्षा से संभव है। यदि प्राथमिक स्तर पर थारू भाषा में शिक्षण सामग्री और शिक्षण दिया जाए, तो न केवल छात्रों की समझ बेहतर होगी, बल्कि वे विद्यालय से भावनात्मक रूप से भी जुड़ाव महसूस करेंगे। बाद के स्तरों पर हिंदी और अंग्रेजी को क्रमिक रूप से जोड़ा जा सकता है, जिससे बहुभाषिक दक्षता भी विकसित हो। इस प्रकार मातृभाषा आधारित शिक्षा थारू छात्रों में शैक्षणिक रुचि, आत्मविश्वास और विद्यालय में टिके रहने की प्रवृत्ति को सशक्त रूप से बढ़ावा दे सकती है।

4.3 आर्थिक दबाव: गरीबी के चलते परिवार लड़कियों को घरेलू या कृषि कार्यों में लगा देते हैं।

4.4 सांस्कृतिक असंबद्धता: स्थानीय परंपराओं से कटे हुए पाठ्यक्रम छात्रों को आकर्षित नहीं कर पाते।

4.5 भेदभाव: ऊँची जातियों और शिक्षकों द्वारा आदिवासी छात्रों के प्रति अपनाया जाने वाला पूर्वाग्रह और भेदभावपूर्ण व्यवहार, शिक्षा प्रणाली के भीतर एक गहरे सामाजिक विभाजन को उजागर करता है। यह केवल शैक्षिक अनुभव को प्रभावित नहीं करता, बल्कि इन छात्रों की आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और सीखने की इच्छा पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। जब शिक्षक या सहपाठी उनके साथ जातिगत भेदभाव, तिरस्कारपूर्ण भाषा या सामाजिक दूरी बनाए रखते हैं, तो इससे आदिवासी छात्रों के मन में अलगाव, हीनता और सामाजिक असुरक्षा की भावना गहराने लगती है। इस तरह का भेदभाव कई बार प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है– जैसे कि उन्हें अलग बिठाना, उनके प्रश्नों को अनदेखा करना, या उनके योगदान को महत्व न देना–जबकि कई बार यह सूक्ष्म लेकिन लगातार होने वाला होता है, जो छात्रों को यह महसूस कराता है कि वे "दूसरे" हैं या मुख्यधारा का हिस्सा नहीं हैं। यह अनुभव धीरे-धीरे शिक्षा से विमुखता, ड्रॉपआउट दर में वृद्धि, और स्कूलिंग की गुणवत्ता में गिरावट का कारण बनता है। इस प्रकार ऊँची जातियों और शिक्षकों द्वारा बरता गया यह पूर्वाग्रह न केवल व्यक्तिगत स्तर पर विद्यार्थियों को हानि पहुँचाता है, बल्कि समग्र रूप से शिक्षा के समावेशी और समानता-आधारित स्वरूप को भी कमजोर करता है। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि शिक्षकों को सामाजिक न्याय, विविधता और जातीय संवेदनशीलता से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, ताकि वे कक्षा में हर छात्र के साथ सम्मानजनक और निष्पक्ष व्यवहार कर सकें।

साथ ही, स्कूलों में सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने वाली गतिविधियाँ और निगरानी तंत्र भी स्थापित किए जाने चाहिए ताकि आदिवासी छात्रों को एक सुरक्षित, सम्मानजनक और सहयोगी शैक्षिक वातावरण मिल सके।

5. सरकारी और NGO हस्तक्षेप

5.1 व्यावसायिक प्रशिक्षण

जनजातीय विकास योजना के अंतर्गत महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और पारंपरिक कौशल के संरक्षण की दिशा में एक अभिनव पहल के रूप में जूट, केला रेशा, जलकुंभी और सिकी घास जैसे स्थानीय, प्राकृतिक संसाधनों से हस्तशिल्प निर्माण का प्रशिक्षण दिया गया है। यह पहल न केवल सतत आजीविका के साधनों को प्रोत्साहित करती है, बल्कि जनजातीय महिलाओं की पारंपरिक कला को आधुनिक बाजारों से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम भी सिद्ध हो रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षकों द्वारा महिलाओं को कच्चे माल की पहचान, उसका उपचार, डिजाइन तकनीक, रंग संयोजन, और तैयार उत्पाद को बाज़ार के अनुरूप आकर्षक रूप देने की विस्तृत जानकारी दी गई। प्रशिक्षण सत्रों में महिलाओं को बैग, टोकरियाँ, मैट, शो-पीस, सजावटी वस्तुएँ, घरेलू सजावट के सामान, और उपहार पैक जैसी वस्तुएँ तैयार करना सिखाया गया। प्रशिक्षण पूरी तरह से व्यावहारिक था, ताकि महिलाएं सीधे कौशल के आधार पर उत्पादन शुरू कर सकें।

5.2 शैक्षणिक योजनाएँ

सर्व शिक्षा अभियान (SSA) और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) जैसी प्रमुख शैक्षिक योजनाओं ने भारत में विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों की बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन योजनाओं के अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तकों और यूनिफॉर्म की व्यवस्था, तथा पोषण युक्त मध्यान्ह भोजन (Mid-Day Meal) जैसी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। थारू समुदाय की छात्राओं के लिए ये योजनाएं एक जीवनरेखा की तरह साबित हुई हैं, जिन्होंने प्राथमिक और मध्य स्तर की शिक्षा तक उनकी निरंतरता सुनिश्चित की है। विशेष रूप से मध्यान्ह भोजन योजना ने न केवल पोषण की दृष्टि से लाभ पहुँचाया है, बल्कि माता-पिता को आर्थिक रूप से भी राहत दी है, जिससे वे अपनी बेटियों को विद्यालय भेजने के लिए अधिक प्रेरित हुए हैं। इसके अतिरिक्त, छात्रवृत्ति योजनाओं ने गरीब और आदिवासी पृष्ठभूमि से आने वाली छात्राओं को स्टेशनरी, कपड़े, और परिवहन जैसे खर्चों को वहन करने में मदद की है। इससे शिक्षा छोड़ने की दर (dropout rate) में उल्लेखनीय कमी आई है, और मिडिल स्कूल तक लड़कियों की उपस्थिति व भागीदारी में सुधार देखने को मिला है। इन योजनाओं के प्रभाव से विद्यालयों में बालिकाओं की संख्या में स्थिर वृद्धि देखी गई है, और कई क्षेत्रों में तो लड़कों की तुलना में लड़कियों की उपस्थिति अधिक रही है। इसके अलावा, बालिका शिक्षा पर केंद्रित विशेष जागरूकता अभियानों, जैसे "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ", ने सामाजिक दृष्टिकोण में भी सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद की है। हालांकि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर नामांकन दर में अब भी चुनौतियाँ बनी हुई हैं, लेकिन SSA और RMSA जैसी योजनाओं ने कम से कम मिडिल स्कूल तक लड़कियों को शिक्षा से जोड़े रखने का एक मजबूत आधार तैयार किया है। यदि इन योजनाओं को सामुदायिक भागीदारी, मातृभाषा आधारित शिक्षण और जेंडर-संवेदनशील प्रशासन से जोड़ा जाए, तो यह आधार और भी मजबूत किया जा सकता है। यह पहल थारू समाज जैसे जनजातीय समुदायों में लड़कियों के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसे और व्यापक बनाने की आवश्यकता है ताकि वे उच्च शिक्षा की ओर भी आत्मविश्वास से अग्रसर हो सकें।

5.3 NGO की भूमिका

नेपाल यूथ फाउंडेशन और BASE ने बाल मजदूरी के खिलाफ अभियान चलाए और अनौपचारिक शिक्षण केंद्रों की स्थापना की।

5.4 डिजिटल साक्षरता और स्वयं सहायता समूह (SHG)

आर्टी राणा जैसी स्थानीय नेताओं ने SHG की स्थापना कर बचत और डिजिटल प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया।

6. संभावनाएं और सर्वोत्तम प्रथाएं

6.1 पाठ्यक्रम में सांस्कृतिक समावेशन: थारू भाषा और स्थानीय कहानियों को शिक्षण में शामिल करने से छात्रों की रुचि बढ़ती है।

6.2 सामुदायिक स्कूल: स्थानीय स्वयंसेवकों द्वारा संचालित स्कूलों में उपस्थिति दर अधिक पाई गई है।

6.3 प्रौद्योगिकी का उपयोग: मोबाइल लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म और व्हाट्सएप-आधारित शिक्षण विशेष रूप से COVID-19 के दौरान उपयोगी रहे।

6.4 प्रेरक व्यक्तित्व: आर्टी राणा जैसी महिलाओं ने सामाजिक मान्यताओं को तोड़कर प्रेरणा दी है।

6.5 हस्तशिल्प के लिए बाज़ार संपर्क: प्रशिक्षण केंद्र अब ऑनलाइन बाज़ारों से जुड़े हैं।

7. केस स्टडी: पलिया तहसील, लखीमपुर खीरी इस क्षेत्र में हाल ही में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ी है:

सरकार द्वारा समर्थित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की यात्रा ने स्थानीय उद्यमों को प्रोत्साहित किया जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल की पहल से व्यावसायिक टूलकिट और कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किए गए

8. नीतिगत सिफारिशें

शैक्षिक सामग्री में थारू संस्कृति का समावेश करें दूरस्थ क्षेत्रों में छात्राओं के लिए छात्रावास का निर्माण करें स्थानीय महिला शिक्षकों की नियुक्ति हो छात्राओं को स्कूल तक पहुंचने के लिए साइकिल या परिवहन सुविधा मिले जनजातीय शिक्षा के लिए बजट बढ़ाया जाए कार्यान्वयन की निगरानी में समुदाय की भागीदारी हो

9. निष्कर्ष

थारू महिलाओं की शिक्षा केवल उनके व्यक्तिगत सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और निर्णय क्षमता के विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यापक सामाजिक परिवर्तन और भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र के समग्र, सतत एवं समावेशी विकास के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक शिक्षित थारू महिला न केवल अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में सक्षम होती है, बल्कि वह स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, परिवार नियोजन तथा बाल शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक विषयों में जागरूकता उत्पन्न कर समुदाय के भीतर सक्रिय नेतृत्व की भूमिका भी निभा सकती है। शिक्षा महिलाओं को अपने अधिकारों की समझ देती है, जिससे वे सामाजिक अन्याय, हिंसा और भेदभाव के विरुद्ध आवाज़ उठा सकें। इसके अतिरिक्त, शिक्षित महिलाएं अगली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बनती हैं, जिससे पूरे समुदाय में शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। हालांकि, थारू समुदाय की महिलाओं को शिक्षा के मार्ग में अब भी अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इनमें बाल विवाह, घरेलू कार्यों का अत्यधिक बोझ, रूढ़िवादी सामाजिक दृष्टिकोण, विद्यालयों की भौगोलिक अनुपलब्धता, आर्थिक संसाधनों की कमी और सांस्कृतिक दूरी जैसी बाधाएँ प्रमुख हैं। इन अवरोधों के कारण न केवल विद्यालय में नामांकन प्रभावित होता है, बल्कि निरंतरता बनाए रखना और उच्चतर शिक्षा तक पहुंच भी कठिन हो जाती है।bइन चुनौतियों के बावजूद, वर्तमान समय में अनेक सकारात्मक संकेत उभर कर आ रहे हैं। यदि सरकार, गैर-सरकारी संगठन, स्थानीय प्रशासन और स्वयं समुदाय एकजुट होकर प्रयास करें, तो इन बाधाओं को व्यवस्थित रूप से दूर किया जा सकता है। इस संदर्भ में सांस्कृतिक संवेदनशीलता एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। थारू समुदाय की विशिष्ट भाषा, जीवनशैली और परंपराओं को समझे बिना यदि शिक्षा संबंधी योजनाएं उन पर थोप दी जाती हैं, तो वे न केवल अप्रभावी सिद्ध होंगी, बल्कि समुदाय में अविश्वास और निष्क्रियता भी उत्पन्न कर सकती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि सभी शैक्षिक योजनाएं एवं कार्यक्रम स्थानीय संदर्भों के अनुरूप डिज़ाइन किए जाएं। उदाहरणस्वरूप:

प्राथमिक शिक्षा में थारू भाषा का समावेश
महिला शिक्षकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण
समुदाय आधारित शिक्षण केंद्रों की स्थापना
माता-पिता और समुदाय को संलग्न करने वाले परामर्श कार्यक्रम

इन उपायों के माध्यम से थारू महिलाओं के लिए एक ऐसा शैक्षिक वातावरण निर्मित किया जा सकता है जो उनकी सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान का सम्मान करता हो और उन्हें समान अवसर प्रदान करता हो। इस प्रकार, शिक्षा केवल थारू महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने का माध्यम नहीं बनती, बल्कि यह सीमावर्ती क्षेत्रों में सामाजिक समावेशन, लैंगिक समानता और सतत विकास की दिशा में एक प्रभावी आधारशिला भी सिद्ध होती है।

10. संदर्भ

1. Census of India. Primary Census Abstract – Data Highlights for Scheduled Tribes. New Delhi: Registrar General & Census Commissioner, India; c2011.
2. Ministry of Tribal Affairs. Annual Report 2021–22 [Internet]. New Delhi: Government of India; c2022 [cited 2025 Jul 15]. Available from: https://tribal.nic.in
3. Planning Commission. Report of the High-Level Committee on Socio-Economic, Health and Educational Status of Tribal Communities of India. New Delhi: Government of India; c2014.
4. National Commission for Scheduled Tribes. Educational Status of Tribal Women in India [Internet]. New Delhi: NCST; c2021 [cited 2025 Jul 15]. Available from: https://ncst.nic.in
5. National Sample Survey Office (NSSO). Household

Social Consumption on Education in India: 75th Round. New Delhi: Ministry of Statistics and Programme Implementation; c2020.
6. Singh KS. People of India: Uttar Pradesh. Vol. XLII. Kolkata: Anthropological Survey of India, Oxford University Press; c1993.
7. UNICEF India. Empowering Tribal Adolescent Girls through Education and Life Skills [Internet]. New Delhi: UNICEF; c2020 [cited 2025 Jul 15]. Available from: https://www.unicef.org/india
8. UDISE+. School Education in India – Unified District Information System for Education Plus (2022–23). New Delhi: Ministry of Education; c2023.
9. International Institute for Population Sciences (IIPS), ICF. National Family Health Survey (NFHS-5), 2019–21: Uttar Pradesh. Mumbai: IIPS; c2021.
10. World Bank. Tribal Education in India: Policy Brief [Internet]. Washington (DC): World Bank; c2018 [cited 2025 Jul 15]. Available from: https://www.worldbank.org
11. Government of Uttar Pradesh. Scheduled Tribe Welfare Annual Report. Lucknow: Department of Social Welfare; c2022.
12. Pradhan A, Verma R. Barriers to Education Among Tribal Girls: A Study in Northern India. International Journal of Social Science Research. 2017;5(2):88-102.
13. Indira Gandhi National Open University (IGNOU). Education and Empowerment of Tribal Women. New Delhi: School of Gender and Development Studies, IGNOU; c2020.
14. CARE India. Improving Learning Outcomes in Marginalized Tribal Communities. New Delhi: CARE India; c2019.
15. Mahanta B. Language and Identity: Role of Mother Tongue in Tribal Education. Journal of Tribal Studies. 2016;12(1).
16. Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. Skilling of Tribal Youth in India. New Delhi: Government of India; c2021.
17. NITI Aayog. Aspirational Districts Programme: Best Practices in Education Sector. New Delhi: Government of India; c2020.
18. Singh R, Patel M. Impact of Social and Cultural Barriers on Girls' Education in Tribal Regions of India. Educational Quest: An International Journal of Education and Applied Social Sciences. 2020;11(1):23–30.
19. Ekta Parishad, Oxfam India. Grassroots Voices: Tribal Women and Access to Education in India. Field Research Report. New Delhi: Ekta Parishad and Oxfam India; c2018.
20. Sharma RK. A Study on Tribal Education in India with Special Reference to Scheduled Tribes. International Journal of Multidisciplinary Research. 2021;9(3):114–127.

Creative Commons (CC) License
This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.